



वैश्वीकरण का महिलाओं की भूमिका और सामाजिक संबंध पर प्रभाव का अध्ययन

सुमन धृतलहरे, पीएच-डी, वाणिज्य विभाग
महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Author

सुमन धृतलहरे, पीएच-डी

E-mail : sumandhritlahare12@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 12/06/2026
Revised on : 13/08/2026
Accepted on : 22/08/2026
Overall Similarity : 02% on 14/08/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

2%

Overall Similarity

Date: Aug 14, 2026 (03:02 PM)
Matches: 53 / 2539 words
Sources: 6

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

वैश्वीकरण ने महिलाओं के जीवन को केवल रोजगार और आय के स्तर पर नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, पारिवारिक संबंध, डिजिटल सहभागिता, सामाजिक पहचान और पर्यावरणीय भूमिकाओं तक प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र उपलब्ध साहित्य एवं प्रदत्त स्रोत-सामग्री के विषयगत विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वैश्विक बाजार, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने महिलाओं के लिए किस प्रकार नए अवसर निर्मित किए हैं और साथ ही किन नई असमानताओं, दोहरे दायित्वों तथा पहचान संबंधी तनावों को जन्म दिया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण महिलाओं के लिए एक समान अनुभव नहीं है। शहरी, ग्रामीण, आदिवासी, प्रवासी और श्रमिक महिलाओं पर इसके प्रभाव अलग-अलग सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भों में दिखाई देते हैं। आर्थिक भागीदारी, डिजिटल नेटवर्क और शिक्षा ने निर्णय क्षमता तथा सार्वजनिक उपस्थिति को बढ़ाया है, परंतु असुरक्षित रोजगार, अवैतनिक देखभाल कार्य, डिजिटल विभाजन और सांस्कृतिक क्षरण जैसी चुनौतियाँ अभी भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण को केवल बाजार में प्रवेश से नहीं, बल्कि संसाधनों, सम्मान, सुरक्षा, निर्णय-निर्माण और सांस्कृतिक स्वायत्तता तक समान पहुँच से जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्य शब्द

वैश्वीकरण, महिला सशक्तिकरण, श्रम भागीदारी, डिजिटल जुड़ाव, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक संबंध.

भूमिका

वैश्वीकरण आधुनिक समाज की उन प्रमुख प्रक्रियाओं में से है जिसने स्थानीय जीवन को वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार, शिक्षा और सांस्कृतिक प्रवाह से जोड़ दिया है। इसका प्रभाव महिलाओं पर विशेष रूप से दिखाई देता है, क्योंकि वे परिवार, श्रम बाजार, समुदाय और संस्कृति के बीच एक साथ अनेक भूमिकाएँ निभाती हैं। व्यापार का विस्तार, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, इंटरनेट और सामाजिक मीडिया ने

महिलाओं के सामने नए अवसर खोले हैं। दूसरी ओर, इन्हीं प्रक्रियाओं ने रोजगार की अनिश्चितता, पारिवारिक दायित्वों के दोहरे बोझ, सांस्कृतिक दबाव और डिजिटल असुरक्षा जैसी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं इसलिए वैश्वीकरण को केवल आर्थिक उदारीकरण या बाजार विस्तार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है, इसे महिलाओं के दैनिक जीवन और सामाजिक संबंधों में हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

Moghadam (1999) ने वैश्वीकरण को लैंगिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि उत्पादन और श्रम बाजार का पुनर्गठन पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित नहीं करता। Kabeer (2004) ने भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने के बावजूद घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का भार प्रायः कम नहीं होता। इसी कारण आर्थिक अवसर और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच अंतर बना रहता है।

शोध उद्देश्य एवं पद्धति

1. वैश्वीकरण के कारण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भूमिकाओं में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
2. शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के बदलते संबंधों तथा पहचान को समझना।
3. चुनौतियों तथा नीतिगत आवश्यकताओं की पहचान करना जो समावेशी महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं।

अध्ययन की पद्धति वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। प्रदत्त अध्याय में प्रयुक्त प्रमुख वैचारिक तर्कों, शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निष्कर्षों को विषयगत रूप से पुनर्गठित किया गया है। अतः यह प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं, बल्कि साहित्य-आधारित शोध-पत्र है। इसकी विश्लेषणात्मक धुरी दो प्रश्नों पर केंद्रित है। क्या वैश्वीकरण महिलाओं की स्वायत्तता बढ़ाता है, और यदि हाँ, तो किन सामाजिक शर्तों के अंतर्गत?

आर्थिक परिवर्तन, श्रम भागीदारी और घरेलू शक्ति-संतुलन

वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर देखा गया है। उत्पादन के अंतरराष्ट्रीयकरण, निर्यात-उन्मुख उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सूक्ष्म उद्यम और डिजिटल कार्य के विस्तार से महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते बने। भारत सहित कई विकासशील देशों में महिलाएँ वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण, खुदरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू सेवा, ई-कॉमर्स और स्वरोजगार से जुड़ी हैं। इससे आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ी और अनेक परिवारों में महिलाओं की आर्थिक भूमिका अधिक स्पष्ट हुई। नियमित या स्वतंत्र आय परिवार के भीतर उनकी निर्णय क्षमता, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और बचत से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकती है फिर भी रोजगार की संख्या बढ़ना अपने आप में समानता की गारंटी नहीं है। Moghadam (1999) ने महिला श्रम के बढ़ते उपयोग को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें अवसर और असमानता साथ-साथ उपस्थित रहते हैं। अनेक महिलाएँ निम्न वेतन, अस्थायी अनुबंध, अनौपचारिक रोजगार या सामाजिक सुरक्षा से वंचित कार्यों में केंद्रित हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में लागत कम रखने का दबाव प्रायः ऐसे श्रम की मांग बढ़ाता है जिसे आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सके। इसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक हो सकती है, पर श्रम अधिकार अपेक्षाकृत कमजोर रहते हैं।

Kabeer (2004) का विश्लेषण बताता है कि कमाई करने के बाद भी महिलाओं का अवैतनिक घरेलू श्रम समाप्त नहीं होता। खाना बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, पानी और ईंधन की व्यवस्था तथा घर के अन्य कार्य अक्सर महिला की जिम्मेदारी बने रहते हैं। इस प्रकार वे वेतनयुक्त और अवैतनिक दोनों प्रकार के श्रम को साथ लेकर चलती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ समय का अभाव और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा जब रोजगार की गुणवत्ता, उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व सुविधाएँ, सामाजिक सुरक्षा और घरेलू श्रम का अधिक न्यायपूर्ण बँटवारा सुनिश्चित हो। प्रवासन भी वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

Sassen (2000) ने महिलाओं के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशिष्ट प्रवृत्ति बताया। घरेलू कार्य, देखभाल, आतिथ्य और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएँ दूसरे शहरों या देशों में काम करती हैं। इससे आय और व्यक्तिगत स्वायत्तता बढ़ सकती है, पर परिवार से दूरी, असुरक्षित काम, कानूनी संरक्षण की कमी और भावनात्मक विस्थापन जैसी समस्याएँ सामने आती हैं इसलिए श्रम भागीदारी को केवल रोजगार दर से नहीं, बल्कि काम की गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता से भी मापना आवश्यक है।

सांस्कृतिक पहचान, परिवार और बदलते सामाजिक संबंध

वैश्वीकरण ने महिलाओं की सांस्कृतिक पहचान को भी गहराई से प्रभावित किया है। टेलीविजन, सिनेमा, विज्ञापन, इंटरनेट और सामाजिक मीडिया के माध्यम से जीवनशैली, सौंदर्य, स्वतंत्रता, उपभोग और करियर से जुड़े वैश्विक विचार स्थानीय समाजों तक पहुँचते हैं। इससे महिलाओं को नए जीवन विकल्पों की जानकारी मिलती है और वे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं पर प्रश्न उठा सकती हैं। वैश्विक संस्कृति ऐसे मानक भी प्रस्तुत करती है जिनसे स्थानीय भाषा, पहनावा, लोकज्ञान और सामुदायिक मूल्य दबाव में आ सकते हैं।

मोहंती (2003) ने यह चेतावनी दी कि सभी महिलाओं के अनुभवों को एक ही वैश्विक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रामीण महिला, शहरी पेशेवर, आदिवासी महिला, प्रवासी श्रमिक और उद्यमी महिला वैश्वीकरण का अनुभव अलग-अलग तरीके से करती हैं। यही विविधता सांस्कृतिक विश्लेषण का मूल आधार है। किसी समाज में आधुनिकता का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकता है, जबकि दूसरे समाज में वह शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार या सामुदायिक निर्णयों में भागीदारी के रूप में दिखाई दे सकती है।

परिवार के स्तर पर भी परिवर्तन स्पष्ट हैं। काम और शिक्षा के लिए महिलाओं की गतिशीलता बढ़ने से विवाह, मातृत्व, घरेलू भूमिकाओं और पीढ़ियों के संबंधों में नए प्रकार की बातचीत शुरू हुई है। युवा महिलाएँ शिक्षा और रोजगार को जीवन की अनिवार्य आकांक्षा मान सकती हैं, जबकि परिवार की पुरानी पीढ़ियाँ इसे परंपरागत व्यवस्था में बदलाव के रूप में देख सकती हैं। यह अंतर हमेशा संघर्ष का रूप नहीं लेता कई परिवार धीरे-धीरे भूमिकाओं का पुनर्समायोजन करते हैं। महिलाओं की आय, शिक्षा और बाहरी नेटवर्क अक्सर परिवार में उनकी आवाज को मजबूत करते हैं।

Hall (1992) की पहचान संबंधी अवधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि वैश्विक संपर्क के दौर में पहचान स्थिर नहीं रहती, बल्कि निरंतर बनती और बदलती है। महिलाएँ आधुनिक शिक्षा, पेशेवर जीवन और डिजिटल संस्कृति को अपनाते हुए अपनी स्थानीय परंपराओं को भी नए रूप में जीवित रख सकती हैं। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान, हस्तकला, कृषि पद्धति, लोककथा और सामुदायिक संस्कारों में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय होती है। Shiva (2005) ने महिलाओं के पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को समुदाय की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय निरंतरता से जोड़ा है। अतः वैश्वीकरण के सकारात्मक लाभ तभी टिकाऊ होंगे जब सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय ज्ञान को पिछड़ेपन के बजाय सामाजिक पूँजी के रूप में देखा जाए।

शिक्षा, तकनीक और डिजिटल जुड़ाव के नए अवसर तथा जोखिम

शिक्षा और तकनीक ने वैश्वीकरण को महिलाओं के दैनिक जीवन में सबसे तीव्र रूप से पहुँचाया है। उच्च शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल प्रशिक्षण और दूरस्थ कार्य के अवसरों ने भौगोलिक सीमाओं को कम किया है। Kabeer (2005) के अनुसार शिक्षा महिलाओं की रणनीतिक जीवन-चयन क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षित महिला केवल रोजगार के लिए अधिक सक्षम नहीं होती, बल्कि स्वास्थ्य, विवाह, परिवार नियोजन, नागरिक भागीदारी और बच्चों की शिक्षा जैसे मामलों में भी अधिक सूचित निर्णय ले सकती है।

डिजिटल तकनीक ने महिला उद्यमिता के नए रास्ते बनाए हैं। घर से चलने वाले छोटे व्यवसाय सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय बाजार से बाहर ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं। ग्रामीण महिला समूह मोबाइल बैंकिंग, बाजार भाव, ऑनलाइन प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। विश्व बैंक की विभिन्न रिपोर्टों में डिजिटल समावेशन को महिलाओं के रोजगार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है। डिजिटल संपर्क विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अवसर देता है जिनकी भौतिक गतिशीलता सामाजिक कारणों से सीमित रहती है।

इसके बावजूद डिजिटल अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उपकरण का स्वामित्व, इंटरनेट की गुणवत्ता, डिजिटल साक्षरता, भाषा और परिवार का समर्थन। ये सभी पहुँच को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण, गरीब और हाशिए पर स्थित महिलाओं के लिए डिजिटल विभाजन एक नई असमानता का रूप ले सकता है। UN Women (2023) ने डिजिटल लैंगिक अंतर को महिला सशक्तिकरण की प्रमुख चुनौती माना है। केवल मोबाइल फोन उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं सुरक्षित उपयोग, साइबर जागरूकता, ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा और स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री भी आवश्यक है।

डिजिटल मंचों ने महिलाओं की सामूहिक आवाज को भी मजबूत किया है। सामाजिक मीडिया के माध्यम से लैंगिक हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव और अधिकारों से जुड़े मुद्दे सीमाओं के पार साझा किए जाते हैं। Fraser (2009) के विचारों से यह समझा जा सकता है कि डिजिटल क्षेत्र वंचित समूहों को सार्वजनिक विमर्श में प्रवेश का नया मंच देता है, किंतु यही दृश्यता साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग, निजता के उल्लंघन और डेटा के दुरुपयोग का जोखिम भी पैदा करती है। तकनीक तभी सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी जब पहुँच के साथ सुरक्षा, कौशल और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

वैश्विक नारीवाद, पर्यावरणीय भूमिका

वैश्वीकरण ने महिलाओं के आंदोलनों और अधिकारों की भाषा को स्थानीय सीमाओं से बाहर पहुँचाया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, महिला नेटवर्क और डिजिटल अभियानों ने समान वेतन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिंसा से सुरक्षा, शिक्षा और प्रजनन अधिकार जैसे प्रश्नों को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाया। Moghadam (2005) ने सीमाओं के पार महिला संगठनों और नेटवर्कों के विस्तार को वैश्विक नारीवादी एकजुटता की महत्वपूर्ण विशेषता माना। इससे स्थानीय आंदोलनों को दृश्यता, संसाधन और वैचारिक समर्थन मिला है फिर भी वैश्विक नारीवाद तभी प्रभावी हो सकता है जब वह स्थानीय सामाजिक संरचनाओं को समझे।

Mohanty (2003) ने पश्चिम-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि वर्ग, समुदाय, जाति, नस्ल, धर्म, क्षेत्र और जीविका की स्थितियाँ महिलाओं के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण या आदिवासी महिला के लिए सशक्तिकरण का अर्थ केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, बल्कि भूमि, जंगल, पानी, आजीविका और सामुदायिक सम्मान तक सुरक्षित पहुँच भी हो सकता है इसलिए स्थानीय वास्तविकताओं की उपेक्षा करने वाला कोई भी सार्वभौमिक मॉडल अधूरा रहेगा।

पर्यावरणीय संदर्भ इस अंतर को और स्पष्ट करता है। ग्रामीण और आदिवासी समाजों में महिलाएँ जल, वन, ईंधन, बीज, खाद्य सुरक्षा और घरेलू उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती हैं। संसाधनों का व्यावसायीकरण, खनन, वनों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन उनके श्रम और जीवन पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। Shiva (2005) ने महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान को जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन से जोड़ा है। IPCC (2022) ने भी यह रेखांकित किया कि भूमि, ऋण और निर्णय-संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण विकासशील क्षेत्रों की महिलाएँ जलवायु जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं।

महिलाएँ केवल प्रभावित समूह नहीं हैं, वे समाधान की सक्रिय भागीदार भी हैं। स्वयं सहायता समूह, महिला सहकारी समितियाँ, जैविक खेती, बीज संरक्षण, हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण और हरित उद्यम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय ज्ञान और आधुनिक बाजार के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से वैश्वीकरण का टिकाऊ रूप वह होगा जिसमें महिलाओं को बाजार में शामिल करने के साथ उनकी सामुदायिक भूमिका, पारिस्थितिक ज्ञान और संसाधनों पर अधिकार भी सुरक्षित किए जाएँ। वैश्विक नेटवर्क उपयोगी हैं, पर उनकी सफलता स्थानीय स्वामित्व और भागीदारी पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैश्वीकरण महिलाओं के लिए न तो पूरी तरह मुक्तिदायक प्रक्रिया है और न ही केवल शोषणकारी। इसका प्रभाव अवसर और असमानता, स्वतंत्रता और दबाव, जुड़ाव और विस्थापन के मिश्रित रूप में सामने आता है। शिक्षा, रोजगार, तकनीक और वैश्विक नेटवर्क ने महिलाओं की सार्वजनिक उपस्थिति, आय के स्रोत, सूचना तक पहुँच और सामाजिक आवाज को बढ़ाया है। अनेक महिलाओं ने इन अवसरों का उपयोग परिवार, समुदाय और स्वयं के जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए किया है साथ ही असुरक्षित काम, कम वेतन, अवैतनिक देखभाल श्रम, डिजिटल विभाजन, सांस्कृतिक दबाव, प्रवासन से उत्पन्न भावनात्मक दूरी और ऑनलाइन हिंसा जैसी समस्याएँ वैश्वीकरण की सीमाओं को उजागर करती हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण की नीति को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

1. महिलाओं के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व सहायता तथा कौशल उन्नयन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
2. अवैतनिक देखभाल कार्य को सामाजिक और नीतिगत मान्यता देते हुए बाल देखभाल केंद्र, सामुदायिक सेवाएँ और परिवार में जिम्मेदारियों के साझा वितरण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

3. डिजिटल सशक्तिकरण के लिए उपकरण से आगे बढ़कर डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, स्थानीय भाषा में सामग्री और महिला उद्यमियों के लिए ई-कॉमर्स प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
4. शिक्षा और कौशल नीति में ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। छात्रवृत्ति, सुरक्षित आवास, परिवहन, डिजिटल सुविधा और स्थानीय रोजगार से शिक्षा का वास्तविक लाभ बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Appadurai, A. (1996) *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press, United States.
2. Fraser, N. (2009) *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press, United States.
3. Hall, S. (1992) The question of cultural identity. In *Modernity and its futures*. Polity Press, United Kingdom.
4. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022) *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. IPCC, Switzerland.
5. Kabeer, N. (2004) *Globalization, labor markets and women's work: Exploring the links*. Institute of Development Studies, United Kingdom.
6. Kabeer, N. (2005) Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24. 06.04.2026
7. Kabeer, N. (2015) *Gender, labour, and rights*. Routledge, United Kingdom.
8. Moghadam, V. M. (1999) Gender and globalization: Female labor and women's mobilization. *Journal of World-Systems Research*, 5(2), 367–388. 04.04.2026
9. Moghadam, V. M. (2005) *Globalizing women: Transnational feminist networks*. Johns Hopkins University Press, United States.
10. Mohanty, C. T. (2003) *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Duke University Press, United States.
11. Sassen, S. (2000) Women's burden: Counter-geographies of globalization and the feminization of survival. *Journal of International Affairs*, 53(2), 503–524. 07.04.2026
12. Shiva, V. (2005) *Earth democracy: Justice, sustainability, and peace*. South End Press, United States.
13. UN Women. (2023) *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, United States.
14. World Bank. (2022) *Digital dividends for women*. World Bank Group, United States.
